

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6 > वैशाख मास में जल दान, नदी स्नान...



**फिर एक बार
मोदी सरकार**

संवरेगा भविष्य मिलेगा रोजगार युवाहितैषी है मोदी सरकार

भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़



सरगुजा के बलरामपुर, कोरबा के करतला और मुंगेली के रोहरा में मुख्यमंत्री ने किया चुनाव प्रचार
शाह के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किये जाने पर बिफरे मुख्यमंत्री साय



मोदी जी के पिटारे में अभी देश के विकास के लिए बहुत कुछ

रायपुर/बलरामपुर/करतला/रोहरा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का चुनावी अभियान जोर-शोर से जारी है। भरी गर्मी में मुख्यमंत्री रोजाना 3-3 जनसभाएं कर रहे हैं, भाजपा प्रत्याशियों के लिए मतदान की बात कर रहे हैं। सरगुजा के बलरामपुर, कोरबा के करतला और मुंगेली के रोहरा में आए जनकुम्भ के बीच कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो को तोड़-मरोड़ कर पेश किये जाने पर श्री साय कांग्रेस पार्टी पर जम कर भड़के। उन्होंने कांग्रेस को मुद्दाबिहीन बताते हुए तरह-तरह के भ्रम फैलाने की बात कही और उसे बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी बताया। सरगुजा के अंतिम छोर बलरामपुर में सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में पहले से ही हार की हताशा साफ दिख रही है। इसलिए हमारे बड़े-बड़े नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं,

सत्ता में आने पर हटा देंगे 50% आरक्षण सीमा: राहुल गांधी

सकरी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले 400 पार का नारा दे रहे थे और अब 150 पार भी नहीं बोल रहे। क्योंकि.. जनता समझ गई है कि भाजपा के लोग 400 पार के नारे की आड़ में संविधान और गरीबों के अधिकार छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण, वोट, अधिकार... ये सभी संविधान की देन हैं। अगर संविधान नहीं रहा तो आदिवासी साथियों के हाथ से जल-जंगल-जमीन गायब हो जाएंगे। हम जिन्हें आदिवासी कहते हैं, भाजपा के लोग उन्हें वनवासी कहते हैं। कांग्रेस के चुनावी वादों पर प्रकाश डालते हुए गांधी ने कहा कि 'इंडिया' के सत्ता में आने के बाद 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटा दी जाएगी। राहुल ने कहा कि हमारे लिए आदिवासी का मतलब- जो देश के सबसे पहले मालिक हैं। लेकिन भाजपा के लोग आपको वनवासी कहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं आपको जल-जंगल-जमीन न मिले। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक सोच है। इसका मतलब है हिंदुस्तान के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन.. जब वे सरकारी चीजों को प्राइवेट करते हैं, आरक्षण को खत्म करते हैं। अनिश्चर जैसी स्क्रीम लाते हैं, आरक्षण को खत्म करते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्क सेक्टर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जगह मिलती थी, लेकिन जैसे ही उसे प्राइवेट किया जाता है, इनको जगह नहीं मिलती। गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्होंने संविधान की पुस्तक को दिखाते हुए कहा, यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, भाजपा के नेता और आरएसएस के लोग बदलना और खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ वह संविधान को खत्म करने में लगे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसे बचाने की कोशिश कर रही है। गांधी ने कहा कि संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह इस देश में गरीबों को अधिकार देता है, उनकी रक्षा करता है और उनके भविष्य की देखभाल करता है। लेकिन भाजपा चाहती है कि इसे फाड़ कर फेंक दिया जाए।

सीपीआईएम और कांग्रेस बंगाल में भाजपा की दो आंखें हैं: ममता

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 अप्रैल को चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और कहा कि इससे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले के अल्पसंख्यक बहुल जंगीपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली में बोलते हुए, ममता ने भाजपा पर मतदान के शुद्धाती चरणों में हार की आशंका के बाद विभाजनकारी रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। जंगीपुर में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा है। बनर्जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ भावना बढ़ रही है और पहले दो चरणों के मतदान के बाद यह स्पष्ट है। जब भी चुनाव होते हैं, वे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए किसी न किसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वे यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि यह एक विशेष समुदाय के खिलाफ है। लेकिन यह यूसीसी राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है और इससे हिंदुओं को किसी भी तरह से फायदा नहीं होगा। ममता ने कहा कि पहले दो चरणों में वोटिंग पेटेंट और प्रतिशत देखने के बाद हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी हार गई है।

शाह फेक वीडियो मामला: समाज में तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठ के सदस्यों में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी ने कहा कि फर्जी वीडियो के जरिए समाज में तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही है। देश में लोकतंत्र, शांति और सद्भाव के लिए मैं देश के लोगों से आग्रह करूंगा कि वे फर्जी वीडियो और तस्वीरों को उजागर करें और पुलिस को रिपोर्ट करें। हमारा सामाजिक न्याय का तरीका समाज में विभेद करने का नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने का है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि समाज को फर्जी वीडियो से बचाना हमारी ज़िम्मेदारी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार का रवैया गरीबों को लेकर क्या होता था, इसका अंदाजा आप उनकी नीतियों से लगा सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हजारों टन अनाज सरकार के गोदामों में सड़ता था। कांग्रेस सरकार उसे गरीबों को देने को तैयार नहीं थी। मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस सरकार अनाज गरीबों में बांटे। भाजपा ने पहले आरोप लगाया था कि तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो प्रसारित किया गया था जिसमें उन्हें एससी-एसटी

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अनिल टुटेजा को राहत नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आईएसएस अनिल टुटेजा के लिए सोमवार का दिन राहत लेकर नहीं आया। पांच दिनों की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें चार मई तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। इस बार अदालत ने उन्हें 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा है। चार मई 2024 को ईडी अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश करेगी। चार मई तक अब उनसे प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच करेगी। कोर्ट से अनिल टुटेजा को राहत नहीं मिलने के बाद अब ईडी उनसे नए सिरे से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इस बारे में ईडी के वकील ने बताया कि अनिल टुटेजा के खिलाफ ईडी को पर्याप्त सबूत मिले हैं। ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने अनिल टुटेजा के सरकारी गवाह बनने के सवाल पर कहा कि इस बात का सटीक जवाब अनिल टुटेजा ही दे सकते हैं। अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार इस केस में सुनवाई चल रही है। इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय को जांच करने के लिए रिमांड मिली थी।

चार सेकेंड लेट नहीं होता तो...चंद्रयान-3 खो गया होता

नई दिल्ली। चंद्रमा पर उतरा भारत का ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में खो गया होता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने खुलासा किया है कि कैसे उन्होंने जुलाई 2023 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने से पहले ही मिशन को बचा लिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया है कि मलबे की वस्तुओं और उपग्रहों के साथ संभावित टकराव से बचने के लिए भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 को लॉन्च-ऑफ के दौरान चार सेकेंड की देरी हुई थी। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि एलवीएम3-एम4/चंद्रयान-3 के लिए लॉन्चिंग में एक मिनट की देरी की गई। ताकि इन दोनों रिकेट्स और सैटेलाइट के सामने आने वाले अंतरिक्ष के कचरे और अन्य उपग्रहों की टक्कर से बचा जा सके। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा चंद्रयान-3 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि, इसके नियोजित प्रक्षेपण को नष्ट क्षण पहले इसरो की सावधानीपूर्वक निगरानी प्रणालियों ने एक संभावित जोखिम का पता लगाया।

तारीख हो गई तय, एक मंच पर दिखेंगे दो पुराने दिग्गज

मुंबई। राज ठाकरे ने मनसे के गुड़ी पड़वा मेले में महायुति को बिना शर्त समर्थन देने का फैसला किया। राज ठाकरे ने साफ किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन का बिना शर्त समर्थन करते हैं, ऐसे में राज ठाकरे महायुति के लिए प्रचार भी करेंगे? इसको लेकर उत्सुकता थी। राज ठाकरे के महायुति के प्रचार के लिए पहली सभा तय हो गई है। राज ठाकरे नारायण राणे के लिए रैली करेंगे। राज ठाकरे की सभा 4 मई को शाम 7 बजे होगी। राज ठाकरे कमकबली में उप अस्पताल के सामने एक सार्वजनिक सभा करेंगे। बीजेपी ने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट से नारायण राणे को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिव सेना से विनायक राजत मैदान में हैं। राज ठाकरे और नारायण राणे जब शिव सेना में थे तब भी उन्होंने साथ काम किया था। अब कोंकण की जनसभा में राज ठाकरे क्या कहेंगे इस पर सभी की निगाहें हैं? रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट पर शिवसेना और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है।

कांग्रेस के घोषणापत्र से मचा है सियासी घमासान

पी. चिदंबरम
ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सद्भावना और सहयोग के भूतपूर्व संकेत के तौर पर कांग्रेस के घोषणापत्र को एक बार फिर से अपनी ओर से लिखने और अपने विचारों को उसमें शामिल करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। उनका मानना है कि राजनीतिक संवाद को बेहतर बनाया जाए। बीते सप्ताह जितना कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा उसके बाद मेरी राय तो यही है।
14 अप्रैल को जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी किया गया था, यह स्पष्ट हो गया था कि मोदी, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज से खुश नहीं थे। समिति ने भी चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लिया कि यह किसी राजनीतिक दल का घोषणापत्र नहीं है, बल्कि किसी एक आदमी की महानता को ब्रह्मजलि है, जिसने पार्टी को तैयार किया है। समिति ने उस दस्तावेज को मोदी की गारंटी का नाम देकर अपनी कृतज्ञता जाहिर कर दी। हालांकि पीएम मोदी ने 'जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं' और मोदी की गारंटी वाली बात इसके जारी होने के कुछ ही घंटों के बाद गायब हो गई। आज न तो कोई भाजपा के घोषणापत्र की बात करता है और न ही अब मोदी की गारंटी की गूंज सुनाई देती है।
पीएम मोदी भी अब मोदी की

गारंटी को नकार नहीं सकते और न ही मसौदा तैयार करने वाली समिति को अक्षम बता सकते हैं। अब उन्होंने नई चाल चलते हुए कांग्रेस के घोषणापत्र को चले चले हुए कांग्रेस के घोषणापत्र को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। यह भारतीय साहित्य की उन महान परंपराओं की तरह ही है, जहां टिप्पणियां किए गए कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मोदी द्वारा कांग्रेस के घोषणापत्र की नए सिरे से राजनीतिक व्याख्या में निर्माकित तथ्य शामिल हैं- कांग्रेस लोगों की जमीन, सोना और अन्य कीमती सामान मुसलमानों में बांटेगी। कांग्रेस व्यक्तियों की संपत्ति, महिलाओं के पास मौजूद सोने और आदिवासी परिवारों के पास मौजूद चांदी का मूल्य निर्धारण करने और उन्हें छीनने के लिए सर्वेक्षण कराएंगे। सरकारी कर्मचारियों की जमीन और नकदी कांग्रेस द्वारा जब्त और वितरित की जाएगी। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला दावा मुसलमानों का है और जब डॉ. सिंह ने यह बात कही तो मैं (गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में) मौजूद था। कांग्रेस आपका मंगलसूत्र और स्त्रीधन छीन लेगी और उन लोगों को दे देगी, जिनके अधिक बच्चे हैं। अगर आपके पास गांव में घर है और आप शहर में एक छोटा सा प्लेटेड खरीदते हैं, तो कांग्रेस उनमें से एक घर छीन लेगी और किसी और को दे देगी। साथ काम करने वालों के बीच

प्रतिस्पर्धा। पीएम मोदी के भरोसेमंद सिपहसालार और सलाहकार, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मॉर्दों की संपत्तियों को जब्त कर लोगों में बांट देगी, जबकि राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस लोगों की संपत्ति हड़प लेगी और उन्हें घुसपैठियों को फिर से बांट देगी। अगले ही दिन, राजनाथ सिंह ने अपनी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था जड़ दिया कि कांग्रेस ने सशस्त्र बलों में धर्म-आधारित कोटा शुरू करने की योजना बनाई थी। जैसे-जैसे टिप्पणीकारों की संख्या बढ़ती गई, वे एक-दूसरे से आगे निकलते गए। दूसरी तरफ मोदी को पता चला कि कांग्रेस %विरासत कर% लागू करने की योजना बना रही थी और उन्होंने इस कर के खिलाफ आवाज उठाई। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी टिप्पणी वाले रणक्षेत्र में कूद पड़ीं और 'विरासत कर' को लेकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया। हालांकि उन्हें जानकारी के अभाव में इस बात के लिए माफ किया जा सकता है कि संपत्ति शुल्क (एक प्रकार का विरासत कर) को 1985 में कांग्रेस सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यह देखना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस के घोषणापत्र पर एक साथ हमला क्यों और कब शुरू हुआ ? 19 अप्रैल को पहले दौर के मतदान के बाद ही पीएमओ और भाजपा में घबराहट फैल गई है। पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में जो हमला शुरू किया, वह उसके बाद से रुके नहीं। भाजपा ने जिन काल्पनिक लक्ष्यों की सूची बनाकर कांग्रेस पर हमला शुरू किया, वह अटपटा सा था। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी खूब शब्दबाण छोड़े। इस बात को लेकर मीडिया का कर्तव्य बनता था कि वह सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अनाज उठाए, लेकिन इसके बजाय, समाचार पत्रों ने विवादास्पद विषयों की 'व्याख्या' की और एक से बढ़कर एक संपादकीय लिखे। टीवी चैनलों ने राजनीतिक पंडितों के साक्षात्कार ले-लेकर चर्चा की। पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया नकली युद्ध कई गुना बढ़ गया।

प्रमुख समाचार

